बैंकिंग क्षेत्र में एनपीए निचले स्तर पर : सीतारमण

अब सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए पहले से कहीं अधिक मजबूत स्थिति

नई दिल्ली, 17 अगस्त. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई हैं. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अब सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए पहले से कहीं अधिक मजबूत स्थिति में हैं.

वित्त मंत्री ने पीएसबी कॉन्फ्लुएंस 2026 के उद्घाटन सत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शीर्ष अधिकारियों को संबोधित करते हुए यह बात कही. दो दिवसीय सम्मेलन में बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जा रही है. सीतारमण ने बताया कि वित्तीय सेवा विभाग ने उनके कार्यकाल में पहली बार सम्मेलन में चर्चा के लिए चुने गए सात विषयों पर विस्तृत शोध दस्तावेज तैयार किए हैं.

उन्होंने विशेष रूप से युवाओं से जुड़े दस्तावेज का उल्लेख करते हुए कहा कि इसमें भारत की युवा आबादी को उम्र और जीवन के अलग-अलग चरणों के आधार पर समझाया गया है. उन्होंने बताया कि भारत की करीब 29 प्रतिशत आबादी 15 से 29 वर्ष के बीच है और बैंकों को अपनी योजनाएं बनाते समय इस बड़ी युवा आबादी को ध्यान में रखना चाहिए.

वित्त मंत्री ने कहा कि सम्मेलन के लिए तैयार किए गए सातों दस्तावेजों में दुनिया के अलग-अलग देशों में अपनाई गई अच्छी व्यवस्थाओं को शामिल किया गया है. इन्हें सम्मेलन में शामिल अधिकारियों को पहले ही उपलब्ध कराया गया है, ताकि चर्चा केवल विचारों तक सीमित न रहे, बल्कि ऐसे सुझाव सामने आएं जिन्हें वास्तव में लागू किया जा सके.

> सीतारमण ने कहा कि यह सम्मेलन ऐसे समय हो रहा है जब 'विकसित भारत' के लिए बैंकिंग क्षेत्र पर एक उच्चस्तरीय समिति के गठन की घोषणा होने की उम्मीद है. सम्मेलन से निकलने वाले सुझाव इस समिति के लिए बैंकिंग क्षेत्र के भविष्य की भूमिका तय करने में उपयोगी हो सकते हैं. एनपीए में आई तेज गिरावट का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकों ने कठिन दौर में अपने खातों की सफाई की प्रक्रिया के जरिए विश्वसनीयता हासिल की है. अब बैंक संकट से निपटने के बजाय मजबूत स्थिति से सुधारों को आगे बढ़ाने की स्थिति में हैं.

नीति आयोग का बड़ा अनुमान

नई दिल्ली, 17 अगस्त. भारत के दूरसंचार और नेटवर्क उपकरण क्षेत्र में तेज वृद्धि की बड़ी संभावनाएं हैं, लेकिन चीन पर भारी आयात निर्भरता के कारण घरेलू उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के लिए तत्काल नीतिगत सहायता की जरूरत है. नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार, इन कदमों से 2035 तक इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी दोगुनी हो सकती है और भारत 50 अरब डॉलर का निर्यात केंद्र बन सकता है. दूरसंचार और नेटवर्क उपकरण क्षेत्र आधुनिक वैश्विक संचार व्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन इस समय यह गंभीर व्यापार असंतुलन का सामना कर रहा है.

अमेरिका-ईरान तनाव के बीच सोने-चांदी में तेजी

एमसीएक्स पर 1 प्रतिशत तक उछले भाव

चांदी की कीमतों में भी अच्छी तेजी दर्ज की गई

नई दिल्ली, 17 अगस्त. पश्चिम एशिया में अमेरिका-ईरान संघर्ष को लेकर जारी अनिश्चितता के बीच भारतीय कमोडिटी बाजार में सोमवार के सत्र में कीमती धातुओं में तेजी देखने को मिली. इस बीच, पीले धातु (सोने) और सफेद धातु (चांदी) की कीमतों में 1 प्रतिशत तक की बढ़त दर्ज की गई.

शुरुआती कारोबार में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर अक्टूबर डिलीवरी वाला सोना पिछले बंद 1,54,506 रुपए से 1,649 रुपए यानी 1.06 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,56,155 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुला, जो कि दिन का हाई रहा. खबर लिखे जाने तक गोल्ड 0.40 प्रतिशत यानी 614 रुपए की तेजी के साथ 1,55,120 रुपए पर ट्रेड करते नजर आया. हालांकि मौजूदा कीमतें अभी भी इस वर्ष के रिकॉर्ड उच्च स्तर 1,80,779 रुपए प्रति 10 ग्राम से काफी नीचे हैं.

चांदी की कीमतों में भी अच्छी तेजी दर्ज की गई. सितंबर डिलीवरी वाला सिल्वर अपने पिछले बंद 2,35,924 रुपए 1,576 रुपए यानी 0.66 प्रतिशत की उछाल के साथ 2,37,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर खुला, और दिन के कारोबार में यह 1.08 प्रतिशत यानी 2,555 रुपए की तेजी के साथ 2,38,479 रुपए का उच्चतम स्तर छुआ.

> चांदी का वार्षिक रिकॉर्ड उच्च स्तर 4,20,048 रुपए प्रति किलोग्राम रहा है, जिससे मौजूदा भाव अभी काफी कम है. सोने और चांदी की कीमतों के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखा है, साथ ही हालिया बढ़त के बाद अस्थिरता और स्थिरीकरण की संभावना पर भी जोर दिया है. इन कारण से सोने और चांदी की कीमतों पर नजर बनी हुई है. पिछले सप्ताह, एमसीएक्स पर सोने के वायदा भाव में लगभग 2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि चांदी में 1.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई.

दूरसंचार उपकरणों का वैश्विक केंद्र बन सकता है भारत

नई दिल्ली, 17 अगस्त. भारत के दूरसंचार और नेटवर्क उपकरण क्षेत्र में तेज वृद्धि की बड़ी संभावनाएं हैं, लेकिन चीन पर भारी आयात निर्भरता के कारण घरेलू उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के लिए तत्काल नीतिगत सहायता की जरूरत है.

नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार, इन कदमों से 2035 तक इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी दोगुनी हो सकती है और भारत 50 अरब डॉलर का निर्यात केंद्र बन सकता है. दूरसंचार और नेटवर्क उपकरण क्षेत्र आधुनिक वैश्विक संचार व्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन इस समय यह गंभीर व्यापार असंतुलन का सामना कर रहा है. लक्षित नीतिगत हस्तक्षेप से यह क्षेत्र राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2025 के सार्वभौमिक कनेक्टिविटी और निर्यात से जुड़े लक्ष्यों को हासिल करने में अहम भूमिका निभा सकता है.

2020 से 2024 के बीच भारत से दूरसंचार और नेटवर्क उपकरणों का निर्यात कुल निर्यात का केवल 0.2-0.3 प्रतिशत रहा. इसका सालाना मूल्य करीब 60 करोड़ से 1 अरब डॉलर रहा. इसके मुकाबले इस क्षेत्र में भारत का सालाना आयात 4-5 अरब डॉलर का रहा, जो कुल आयात का 0.7-1.1 प्रतिशत है.

रिपोर्ट में कहा गया कि महत्वपूर्ण उपकरणों और घटकों, जैसे 4जी/5जी एंटीना और सिग्नल प्रोसेसर, के लिए भारत 80 प्रतिशत से अधिक आयात पर चीन पर निर्भर है.

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना में वेकोलि को राष्ट्रीय सम्मान

नई दिल्ली, 17 अगस्त। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के बेहतर संचालन और युवाओं के कौशल विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (वेकोलि) को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है.

भारत सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की ओर से आयोजित 'प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना सहयोगी कंपनी सम्मान समारोह' में वेकोलि को 'सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम सहयोगी' पुरस्कार प्रदान किया गया.

यह सम्मान युवाओं को प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार से जुड़े अवसर उपलब्ध कराने के क्षेत्र में वेकोलि के उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया गया.

नई दिल्ली में आयोजित समारोह में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की सचिव डॉ. पल्लवी जैन गोविल ने वेकोलि के निदेशक (वित्त एवं मानव संसाधन) श्री बिक्रम घोष को यह सम्मान प्रदान किया. उन्होंने कंपनी की ओर से पुरस्कार ग्रहण किया.

इस अवसर पर वेकोलि के अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत कंपनी ने तकनीकी क्षेत्रों के युवाओं के लिए कुल 150 प्रशिक्षण अवसर उपलब्ध कराए हैं.

इन अवसरों में खनन अभियंत्रण में डिप्लोमा के 45, खनन अभियंत्रण में स्नातक के 25 तथा विद्युत अभियंत्रण में स्नातक और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के विद्युत प्रशिक्षुओं के लिए 80 अवसर शामिल हैं. वेकोलि दूरस्थ कोयला क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं को प्रशिक्षण और करियर विकास के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार कार्य कर रहा है.

> कंपनी का उद्देश्य युवाओं को व्यावहारिक औद्योगिक अनुभव के साथ जरूरी कौशल प्रदान करना है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो सकें.

2035 तक 50 अरब डॉलर का टेलीकॉम निर्यात हब बनेगा भारत

टेलीकॉम उपकरण निर्यात में भारत बनेगा 50 अरब डॉलर का केंद्र

चीन पर निर्भरता घटाकर दूरसंचार और नेटवर्क में तेजी की संभावनाएं

नई दिल्ली, 17 अगस्त. भारत के दूरसंचार और नेटवर्क उपकरण क्षेत्र में तेज वृद्धि की बड़ी संभावनाएं हैं, लेकिन चीन पर भारी आयात निर्भरता के कारण घरेलू उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के लिए तत्काल नीतिगत सहायता की जरूरत है.

नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार, इन कदमों से 2035 तक इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी दोगुनी हो सकती है और भारत 50 अरब डॉलर का निर्यात केंद्र बन सकता है. रिपोर्ट के अनुसार, दूरसंचार और नेटवर्क उपकरण क्षेत्र आधुनिक वैश्विक संचार व्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन इस समय यह गंभीर व्यापार असंतुलन का सामना कर रहा है. लक्षित नीतिगत हस्तक्षेप से यह क्षेत्र राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2025 के सार्वभौमिक कनेक्टिविटी और निर्यात से जुड़े लक्ष्यों को हासिल करने में अहम भूमिका निभा सकता है. 2020 से 2024 के बीच भारत से दूरसंचार और नेटवर्क उपकरणों का निर्यात कुल निर्यात का केवल 0.2-0.3 प्रतिशत रहा. इसका सालाना मूल्य करीब 60 करोड़ से 1 अरब डॉलर रहा. इसके मुकाबले इस क्षेत्र में भारत का सालाना आयात 4-5 अरब डॉलर का रहा, जो कुल आयात का 0.7-1.1 प्रतिशत है.

5 लाख कुशल रोजगार पैदा होंगे

नीति आयोग के अनुसार, ऐसी सहायता जारी रहने से दूरसंचार और नेटवर्क उपकरण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी 1-1.5 प्रतिशत तक पहुंच सकती है. इससे करीब 5 लाख कुशल रोजगार पैदा होने और 2035 तक भारत को 50 अरब डॉलर का दूरसंचार उपकरण निर्यात केंद्र बनाने में मदद मिल सकती है. रिपोर्ट में कहा गया कि मजबूत सरकारी हस्तक्षेप घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.

वीआईटी चेन्नई में 14वां सालाना दीक्षांत समारोह मना

चेन्नई, 17 अगस्त। वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी , चेन्नई ने अपना 14वां सालाना दीक्षांत समारोह मनाया। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पूर्व सचिव डॉ. टी. रामासामी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए; बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (पब्लिशिंग) और बोर्ड मेंबर मोहित जैन %गेस्ट ऑफ़ ऑनर% थे; और दक्षिण भारत में श्रीलंका के डिप्टी हाई कमिश्नर डॉ. गणेशनथन गीथिश्वरन विशेष अतिथि के तौर पर शामिल हुए।

वीआईटी के संस्थापक और चांसलर डॉ. जी. विश्वनाथन ने दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की।

समारोह में वीआईटी के वाइस प्रेसिडेंट डॉ. शंकर विश्वनाथन और डॉ. जी.वी. सेल्वम, वाइस चांसलर डॉ. वी.एस. कंचना भास्करन, वीआईटी चेन्नई के प्रो-वाइस चांसलर डॉ. टी. त्यागराजन, वीआईटी वेल्लोर के प्रो-वाइस चांसलर डॉ. पार्थ सारथी मल्लिक, वीआईटी चेन्नई के डायरेक्टर डॉ. के. सत्यनारायणन, वीआईटी के रजिस्ट्रार डॉ. जयभारती टी. और वीआईटी चेन्नई के एडिशनल रजिस्ट्रार डॉ. पी.के. मनोहरन भी शामिल हुए।

सदर में तनिष्क के नए शोरूम की शुरुआत

नवभारत, जबलपुर। सदर चौपाटी के सामने कल नागपंचमी के शुभ अवसर पर तनिष्क के नए शोरूम का उद्घाटन किया गया। टाटा समूह द्वारा प्रवर्तित भारत के सबसे बड़े और विश्वसनीय ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क के 20 वर्ष पुराने सदर मेन रोड स्थित शोरूम को इस नए, बड़े और बेहतर स्वरूप में स्थानांतरित किया गया है, जिसका उद्घाटन कैंट विधानसभा के विधायक अशोक रोहणी द्वारा तनिष्क कंपनी के रीजनल बिजनेस मैनेजर्स गौरव बोरा और दिव्या पटेल की उपस्थिति में किया गया। नए शोरूम में पुराने शोरूम की तुलना में दुगनी जगह और दुगना आभूषण कलेक्शन प्रदर्शित किया गया है तथा मध्य भारत में पहली बार हीरों की जांच करने के लिए जर्मनी से आयातित कैरेट मीटर भी लगाया गया है जहाँ ग्राहक कहीं से भी ख़रीदे गए हीरों की निशुल्क जांच करवा सकेंगे। स्टोर लॉन्च के

अवसर पर नए कलेक्शंस के साथ कम्पनी ने शुद्ध सोने के आभूषण, कुन्दन पोलकी एवं रत्नजड़ित आभूषणों पर शगुन 101 एवं बनवाई पर 20 प्रतिशत तक का डिस्काउंट और प्राकृतिक प्रमाणित हीरे के आभूषणों पर 25 प्रतिशत की छूट का ऑफर 19 अगस्त तक दिया है, जिसके तहत ग्राहक कहीं से भी खरीदे गए अपने पुराने आभूषणों को 100 प्रतिशत मूल्य पर बदलकर प्राकृतिक हीरे के आभूषण क्रय कर सकते हैं या सोने के आभूषण भी नियमानुसार ले सकते हैं। इस अवसर पर माँ दरबार गढ़ा के गुरुजी अरुण शर्मा, खटवानी समूह के चेयरमैन राम चंद खटवानी, डायरेक्टर्स रोहित खटवानी, सीमा खटवानी, रुशील खटवानी, तनिष्क एरिया मैनेजर्स हेमंत वादकर, सुनील राजपूत और शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

समाचार विशेष

केरल में भाजपा को बड़ा झटका

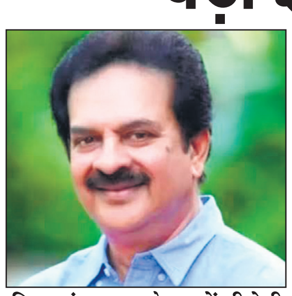

तिरुवनंतपुरम. केरल में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है. यहां एक्टर एस. देवन ने कनाचिकुलंगरा देवी मंदिर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान केरल बीजेपी के उपाध्यक्ष पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने की घोषणा की.

उन्होंने मंदिर के कार्यक्रम में अपना भाषण खत्म करते हुए यह घोषणा की. इस कार्यक्रम में श्री नारायण धर्म परिपालन योगम के महासचिव वेल्लापल्ली नटेसन और बीजेपी नेता बी. राधाकृष्ण मेनन भी मौजूद थे. बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हुए देवन ने कहा, मैं जिस राजनीति में यकीन करता हूं, वह श्री नारायण गुरु के आदर्शों, सिद्धांतों और कार्यक्रमों पर आधारित है. केरल में बीजेपी से जुड़ने के बाद पिछले 5 सालों में मुझे एहसास हुआ है कि मैं उस रास्ते पर नहीं चल पाया. मुझे लगा कि मेरी राजनीतिक सोच अलग थी, और मुझे इसका पक्का यकीन हो गया. मैंने अपना इस्तीफा लिख दिया है और उपाध्यक्ष पद के साथ-साथ भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता भी छोड़ रहा हूं. सभा को संबोधित करते हुए देवन ने कहा कि उन्होंने 2004 और 2006 में चुनाव लड़ा था, लेकिन दोनों बार हार गए. उन्होंने कहा, इसी मंच से यह घोषणा करने का फैसला मैंने यहां बैठने के बाद ही लिया. अपनी बात खत्म करते हुए देवन ने कहा, मैंने बीजेपी के उपाध्यक्ष पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के लिए पत्र लिख दिया है.

हालांकि बीजेपी नेता बी. राधाकृष्ण मेनन ने देवन के इस्तीफे की घोषणा के लिए मंदिर के कार्यक्रम को चुनने पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि देवन ने भारत को 2047 तक दुनिया में सबसे आगे ले जाने की बीजेपी की कोशिशों का हिस्सा न बनने का फैसला क्यों किया.

2021 में भाजपा के साथ आए थे देवन

बता दें कि एक्टर एस देवन ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत केरल पीपल्स पार्टी बनाकर की थी, जिसका नाम 2020 में बदलकर नवा केरल पीपल्स पार्टी कर दिया गया था. उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक के बाद 2021 में अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय कर दिया, जिसके बाद उन्हें पार्टी का राज्य उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया.

भाजपा का चुनावी रणनीति में बड़ा बदलाव

निकाय से लोकसभा तक जेन-जी को साधने की तैयारी

जयपुर. राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी रणनीति को नई दिशा देते हुए जेन-जी यानी युवाओं को अपने राजनीतिक एजेंडे का मुख्य केंद्र बनाने का निर्णय लिया है. पार्टी का लक्ष्य स्थानीय निकाय चुनावों से लेकर लोकसभा तक के सफर में युवा मतदाताओं को मजबूती से अपने साथ जोड़ना है. इसके लिए सत्ता और संगठन दोनों ही स्तरों पर विशेष प्रयास किए जा रहे हैं.

पार्टी की योजना डिजिटल युग की पीढ़ी की आकांक्षाओं और

उनकी जरूरतों को समझते हुए उन्हें मुख्यधारा की राजनीति में शामिल करने की है. यह कदम न केवल आगामी चुनावों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इसे भविष्य की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करने की एक दूरगामी रणनीति के रूप में देखा जा रहा है.

युवा मतदाताओं की बढ़ती संख्या और उनकी सक्रियता को देखते हुए भाजपा अब अपनी कार्यशैली में बदलाव ला रही है. संगठन के भीतर युवाओं को जोड़ने के लिए सोशल मीडिया और जमीनी स्तर पर नए कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं. पार्टी का मानना है कि यदि युवाओं को स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व और अवसर दिए जाएं, तो वे भविष्य के कुशल नेतृत्व के रूप में उभर सकते हैं. इससे न केवल पार्टी का आधार बढ़ेगा, बल्कि युवाओं का राजनीति के प्रति नजरिया भी सकारात्मक होगा.

युवाओं के बीच अपनी पैठ

> राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राजस्थान में जनसांख्यिकीय बदलाव को देखते हुए यह कदम बेहद जरूरी है. भाजपा का प्रयास है कि वह युवाओं के बीच अपनी पैठ बनाकर एक ऐसा मजबूत वोट बैंक तैयार करे जो लंबे समय तक पार्टी के साथ बना रहे. इसके लिए शिक्षा, रोजगार और तकनीक जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है. आने वाले समय में पार्टी की कोशिश है कि वह युवाओं की भाषा में संवाद करे.

विशेष | कुछ समय से महिलाओं के प्रति अपराध में बढ़ोतरी देखी गई है

बिहार में क्या शराबबंदी खत्म होगी?

पटना. यह सवाल इसलिए है क्योंकि एक केंद्रीय एजेंसी नेशनल कौंसिल ऑफ एप्लायड इकोनॉमिक्स एंड रिसर्च यानी एनसीएईआर ने एक सर्वे किया है, जिसमें कहा गया है कि बिहार में शराबबंदी से बहुत नुकसान है और इसके अनुपात में फायदा बहुत बहुत कम है.

एनसीएईआर का कहना है कि शराबबंदी को यह कह प्रचारित किया गया कि इससे घरेलू हिंसा में और महिलाओं के प्रति अपराध में कमी आई है लेकिन असल में ऐसा नहीं है. इस सर्वे के मुताबिक पिछले कुछ समय से महिलाओं के प्रति अपराध में बढ़ोतरी देखी गई है. इसके अलावा सरकार को वित्तीय नुकसान का भी बड़ा आंकड़ा

बताया गया है. कहा गया है कि शराबबंदी से राजस्व का नुकसान हो रहा है और इस कानून को लागू करने में जो खर्च हो रहा है वह भी बहुत बड़ा है.

तभी यह चर्चा शुरू हो गई कि क्या बिहार की भाजपा सरकार नीतीश कुमार द्वारा लागू शराबबंदी खत्म कर सकती है? हालांकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इससे इनकार किया है. फिर भी केंद्रीय एजेंसी के सर्वे को आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता है. इस बीच नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है. पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरोप लगाया है कि यह सर्वे शराब कंपनियों ने कराया है. जाहिर है जद ने एक स्टैंड ले लिया है कि वह शराबबंदी खत्म नहीं होने देगी. सरकार को वित्तीय नुकसान और राजनीतिक नफा नुकसान को पलड़े पर रख कर तौलना होगा. अगर जनता दल यू तैयार नहीं होती है तो सरकार इस मामले में पहल नहीं करेगी.

मान सरकार का दांव, अमृतपाल भी बना फैक्टर

चंडीगढ़. पंजाब में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है. इसके लिए सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिश अभी से शुरू हो गई है. जिससे राजनीतिक माहौल गरमा चुका है. हाल के दिनों में पंजाब की राजनीति में सिख बंदियों की रिहाई का मामला तेज होता नजर आया है.

पंजाब सीएम भगवंत सिंह मान ने जगतार सिंह हवारा के पैरोल की मांग तेज की है. दूसरी ओर अकाली दल बलवंत सिंह राजोआणा के समर्थन में मोर्चा खोल चुकी है. इन दोनों प्रमुख दलों के बीच अमृतपाल सिंह का फैक्टर भी तेज नजर आ रहा है. इससे चुनाव से पहले पंजाब की राजनीति नए बदलाव की ओर जाता दिख रहा है.

दरअसल पंजाब चुनाव से पहले बंदी सिखों का मुद्दा फिर से राजनीतिक चर्चा के केंद्र में आ गया है. लेकिन यह केवल कैदियों की रिहाई पर बहस तक सीमित नहीं है. यह एक बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत है. बदलाव यह कि पंथक राजनीति पर अब शिरोमणि अकाली दल का एकाधिकार नहीं रही. अकाली दल ने पूर्व पंजाब पुलिस अधिकारी बलवंत सिंह राजोआना के समर्थन में खुलकर मोर्चा संभाला है, जबकि भगवंत मान सरकार ने जगतार सिंह हवारा के मामले को मानवीय और राजनीतिक मुद्दे के रूप में उठाया है. वहीं अमृतपाल सिंह का खेमा भी बंदी सिखों के मुद्दे के जरिए अपना राजनीतिक आधार मजबूत करने की कोशिश कर रहा है. दूसरी ओर दमदमी टकसाल राज्यभर में अपना संगठनात्मक ढांचा खड़ा कर रही है, जो भविष्य में उसे राजनीतिक प्रभाव भी दे सकता है. उल्लेखनीय हो कि जगतार सिंह हवारा और बलवंत सिंह राजोआना दोनों 1995 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए सिख कैदी हैं.

केवल पंथक राजनीति ने नहीं टिक सकेगी अकाली

अकाली दल के सामने एक विरोधाभासी स्थिति है. पार्टी को अपनी प्रासंगिकता दोबारा हासिल करने के लिए पंथक मुद्दों की जरूरत है, लेकिन अब वह यह मानकर नहीं चल सकती कि किसी पंथक मुद्दे को उठाने भर से उस पर उसका राजनीतिक स्वामित्व स्थापित हो जाएगा. हर बार जब अकाली दल इस क्षेत्र में वापसी की कोशिश करता है, कोई दूसरा राजनीतिक खिलाड़ी भी मैदान में आ जाता है. अमृतपाल सिंह का खेमा इस प्रतिस्पर्धा को और जटिल बनाता है.